जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। चीनी के बढ़ती कीमतों को लेकर सरकार की तत्परता से चीनी उद्योग में बेचैनी व्याप्त है। उन्हें डर है कि भारी स्टॉक होने के बावजूद कहीं सरकार जल्दबाजी में चीनी आयात जैसे कदम न उठा ले। पिछले पांच सालों की लंबी मंदी के बाद बाजार में सुधार के रुख से उद्योग ने राहत महसूस की है। लेकिन कीमतें बढ़ते ही सरकार ने एहतियाती कदम उठाते हुए चीनी का स्टॉक सीमा निर्धारित कर दी है।

सरकार की तेजी से चीनी उद्योग सशंकित है। दरअसल, आगामी गन्ना वर्ष में चीनी के उत्पादन में गिरावट का अनुमान लगाया गया है। गंभीर सूखे की चपेट में होने की वजह से महाराष्ट्र में जहां 30 लाख कम चीनी का उत्पादन होने का अनुमान है, वहीं कर्नाटक में आठ से 10 लाख टन कम चीनी का उत्पादन होगा। इन दोनों राज्यों का सूखा प्रभावित क्षेत्र गन्ना उत्पादक है। यहां गन्ने की बुवाई का रकबा कम हो सकता है।

चालू पेराई सीजन के कुल 2.50 करोड़ टन चीनी उत्पादन के मुकाबले अगले गन्ना वर्ष में उत्पादन घटने का अनुमान चीनी बाजार को प्रभावित कर सकता है। हालांकि भारतीय चीनी मिल संघ (इस्मा) का कहना है कि अगले साल के लिए कैरीओवर ओपनिंग स्टॉक 70 लाख टन रहने वाला है।

इस्मा के अध्यक्ष तरुण साहनी की मानें तो चालू मानसून सीजन में अच्छी बारिश का अनुमान लगाया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में अच्छी गुणवत्ता वाले 238 प्रजाति के गन्ने की खेती का रकबा बढ़ने से उत्पादकता दोगुना हो सकती है। चीनी की रिकवरी दर में भारी वृद्धि (12 से साढ़े बारह फीसद) हो सकती है। इससे महाराष्ट्र और कर्नाटक में कम उत्पादन की कमी को यहां से पूरा किया जा सकता है। साहनी का कहना है कि देश में चीनी का पर्याप्त स्टॉक है। उनका कहना है कि चीनी मूल्य को विनियमित करने की जरुरत है।

इस्मा की आयोजित कार्यशाला में हिस्सा लेने आये जागृति किसान मंच के संयोजक डाक्टर सुधीर पंवार ने स्पष्ट किया है कि चीनी का बाजार में इतना मूल्य जरुर होना चाहिए, जिससे किसानों के गन्ने का भुगतान आसानी से हो जाए। पिछले कई सालों से गन्ना किसान और चीनी उद्योग बड़ी चुनौतियों का मुकाबला कर रही हैं।